Cooperation of Pubdic Sector Oil and Natural Gas Companies with foreign companies

1387. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the 'Navbharat Times' dated August 6, 1994 to the effect that public sector oil and natural gas companies have been cooperating with foreign companies in respect of their sales instead of holding a competition with them;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) the effects thereof on public sector companies?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (d) The news-item appeared in the Navbharat Times dated August 16, 1994. In view of liberalisation of marketing of certain petroleum products, the Government oil companies have formed the following Joint Venture Companies for manufacture and marketing of lubricants:—

1. IOC & Mobil . (Indo-Mobil)
2. BPC & Shell . (Bharat-Shell)
3. IBP & Caltex . (IBP-Caltex Limited)
4. IOC, Balmer Lawrie & Nyco
5. Balmer Lawrie & Fuch.

Bharat Shell have also imported 7250 MTs of LPG with the assistance of Bharat Petroleum Corporation Limited. IBP-Caltex have also planned to enter into the marketing of LPG and to develop port facilities. Indian Oil Corporation Limited has further entered into a MOU with Mobil for development of import facility at Haldia. Similarly Hindustan Petroleum Corporation Limited is discussing with certain Private Sector Parties including some foreign companies to form a Joint Venture Company for development of infrastructure. The Public Sector Oil Companies have signed MOUs with 71 parties for facilitating import of kerosene and with 11 parties for facilitating import of LPG and also allowed them to use their facilities for import of these products.

Such tie-ups with foreign multinationals have been entered into with a view to obtaining the latest and state-of-art technology and capital inflow in the respective fields and expanding the business and facing competition effectively. With these tie ups, the PSUs will be in a position to more effectively compete with the foreign companies which would also be entering into the country in areas which have been liberalised. The benefit of the business by these JVCs will also accrue to the PSUs.

राशन कार्ड धारकों को एल०पी०जी० कनेक्शनों का आवंटन

1388. श्री रामजी लाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एल०पी०जी० कनेक्शन केवल उन व्यक्तियों को दिये जाते हैं, जिनके नाम शहरों में राशन कार्ड में दर्ज हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गांवों में राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध भेद भाव बरते जाने के क्य कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पिछले कुछ महीनों के दौरान इस संबंध में किसी समिति का गठन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार देश में शहरी और ग्रामीण लोगों को बिना किसी भेदभाव के कब तक एल०पी०जी० का आबंटन शुरू करने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (घ) शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने के लिए आवास के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है ।

उत्पाद की कमी के कारण फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप चरणबद्ध ढंग से व्यवहार्यता की शर्त पर केवल उन शहरी क्षेत्रों में खोली जाती हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 और अधिक हो । सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरक अपने विपणन क्षेत्र में रहने वाले ग्राहकों के नाम दर्ज करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन केवल संसद सदस्यों की सिफारिश पर दिए जाते है । ये ग्रामीण क्षेत्र उन शहरी क्षेत्रों के आस पास के पर्वतीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के कार्यक्षेत्र का विस्तार उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए किया जाता है । फिलहाल उत्पाद की कमी के कारण गांवों में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलना संभव नहीं है । परन्तु सरकार ने तेल कंपनियों को लगभग 20,000 अथवा कम की जनसंख्या वाले शहरों में नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की व्यवहार्यता बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल करने के अनुदेश दिए हैं । सरकार ने निजी एजेंसियों को समांतर विपणन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपनी पसंद के किसी भी बाजार में बाजार निर्धारित मूल्यों पर एल०पी०जी० की बिक्री की अनुमति भी दे दी है ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये पेट्रोल पंपों का आवंटन

1389. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 1994 तक की अवधि के दौरान हाल ही में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पेट्रोल पम्पों के कितने विज्ञापन जारी किये गये ;

(ख) इसमें से किन किन आवेदकों को, जिलेवार ये पेट्रोल पम्प आबंटित किए गये ; और

(ग) ऐसे आबंटनों के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से ग) 4 जनवरी, 93 से 31 दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 51 खुदरा बिक्री केन्द्रों के विज्ञापन जारी किए गए थे। उपर्युक्त में से विभिन्न जिलों में 38 स्थानों के लिए आशयपत्र जारी किए गए हैं ।

तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद तेल चयन बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित तेल कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया जाता है ।

Relaxation in the criteria for LPG distributor agencies in hill areas

1390. SHRI RATNABAHADUR RAI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for making certain relaxation in the criteria meant for the LPG distributor agencies keeping the topographical constraints in hill areas;

(b) if so, the details thereof; and